

मैसर्स मेडचल केमिकल एण्ड फार्मा प्राईवेट लिमिटेड

बनाम

मैसर्स बायोलोजिकल ई. लिमिटेड और अन्य

फरवरी 25, 2000

[जी.बी.पटनायक एण्ड उमेश सी. बनर्जी, जे.जे.]

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973

धारा 482-अनुबंध के उल्लंघन के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई- उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि शिकायत किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करती है-अपील पर यह माना गया, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सीमित और प्रतिबंधित है और उसे उचित सावधानी बरतनी चाहिए- शिकायत का परीक्षण संपूर्णतया लगाए गए आरोपों के आधार पर प्रकट होना चाहिए-अपराध प्रथम दृष्टया प्रकट होना चाहिए। उच्च न्यायालय को इसकी सत्यता की जांच करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है-यदि कोई अपराध प्रकट नहीं हुआ है तो कार्यवाही को रद्द करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए-मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में शिकायत ने अपराध को घटित होने का खुलासा किया है- इसलिए शिकायत और अभियोजन पुनर्स्थापित किया गया।

भारतीय दण्ड संहिता 1860- धारा 415, 418 और 420-आवश्यक तत्व-माना गया, वादा करते समय दोषी इरादा एक आवश्यक घटक है, ना कि बाद में वादा पूरा करने में विफलता

वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता-माना गया, न्यायालय यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है कि केवल नागरिक उपचार उपलब्ध है तो आपराधिक मुकदमा पूरी तरह से वर्जित है।

अपीलकर्ताओं और उत्तरदाता ने एक समझौता किया था, जिसके तहत उत्तरदाता कच्चे माल की लगातार आपूर्ति के लिए जिम्मेदार थे, ताकि अपीलकर्ता की विनिर्माण गतिविधियों में कोई बाधा ना आए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि समझौते के अनुसार उचित आपूर्ति नहीं की गयी है, जिससे भारी नुकसान हुआ और इसकी जानकारी आरोपी व्यक्तियों को भी थी। धारा 120 बी, 418, 415 व 420 सपठित धारा 34 औईपीसी के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गयी। उच्च न्यायालय ने सीऔरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द किया कि शिकायत में किसी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं किया गया है। इसलिए यह अपील।

अपील की अनुमति देना और आपराधिक कार्यवाही बहाल करना, इस न्यायालय के द्वारा माना गया

1. शिकायत प्राप्त करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 में परिकल्पित अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग या रद्द किया गया आरोप-पत्र एक नियम के बजाय एक अपवाद है और प्रारंभिक चरण में रद्द करने के लिए मामले को दुर्लभ से दुर्लभतम माना जाना चाहिए ताकि अभियोजन को बाधित न किया जा सके। क्षेत्राधिकार सीमित और प्रतिबंधित है और इसका अनुचित विस्तार न तो व्यावहारिक है और न ही आवश्यक है। यदि शिकायत पर गौर करने पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि शिकायत या आरोप पत्र में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया किसी अपराध का गठन या खुलासा नहीं करते हैं जैसा कि आरोप लगाया गया है, तो उम्मीद पर खरा उतरने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए लोगों की मदद करें और कानून के तहत आवश्यक स्थिति से निपटें। निराश वादियों को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अपनी प्रतिशोध की भावना को उजागर करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाना चाहिए और ऐसी जांच को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह न्याय की अवधारणा के विपरीत है, जो सर्वोपरि है। [1172-बी-एफ]

2. यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि सीओरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिकायत की पूरी तरह से जांच शिकायत में लगाए गए आरोप के आधार पर की जानी चाहिए और उस स्तर पर उच्च न्यायालय के पास मामले में जाने या इसकी सत्यता की जांच करने का कोई

अधिकार या क्षेत्राधिकार नहीं है। शिकायत पर जो कुछ भी दिखाई देता है, उस पर बिना किसी आलोचनात्मक परीक्षण के विचार किया जाएगा, लेकिन अपराध शिकायत पर प्रथम दृष्टया दिखाई देना चाहिए। [1180-ए-बी]

श्रीमती नागावा वि. वीरन्ना शिवलिंगप्पा कोंजुल्गी, [1976] 3 एससीसी 736, पर भरोसा किया।

3. धारा 418 और 420 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, वादा करते समय दोषी इरादे एक आवश्यकता और एक आवश्यक घटक है और बाद में वादे को पूरा करने में विफलता धारा 418 के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगी या 420. मेन्स रिया धारा 420 धोखाधड़ी के प्रावधानों के तहत अपराध के आवश्यक तत्वों में से एक है। [1179-सी]

रामजस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1970] 2 एससीसी 740; प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार, [1985] एससीसी सीऔरएल 180 तथा एल.वी. जाधव बनाम शंकरराव अबासाहेब पवार, [1983] 4 एससीसी 231, पर भरोसा किया।

4.1. यह अच्छी तरह से तय है कि शिकायत में क्या आरोप होंगे प्रथम दृष्टया स्वीकार किया जाना

मेडचल केमिकल एण्ड फार्मा प्राईवेट लिमिटेड बनाम मैसर्स बायोलोजिकल ई.
लिमिटेड 1171

चाहिए और जो सत्य या मिथ्या नहीं होगा उस स्तर पर न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा। मुकदमे में पेश किए गए सबूत यह तय करने में सहायता करेंगे कि शिकायत में लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं। [1181-सी]

4.2. उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग के मामले में, एकमात्र आवश्यकता यह देखना है कि क्या कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का पूर्ण दुरुपयोग होगा। संहिता में जांच, आरोप और मुकदमे के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया शामिल है, और यदि उच्च न्यायालय कानून की ज्ञात प्रक्रिया पर रोक लगाना चाहता है, तो उसे शिकायत को रद्द करने के लिए उचित सावधानी और बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। [1181-जी-एच]

नागपुर स्टील एंड अलॉय प्रा. लिमिटेड बनाम पी. राधा कृष्ण, [1997] एससीसी सी और एल 1073 और ट्रिसन्स केमिकल इंडस्ट्री बनाम राजेश अग्रवाल और अन्य, [1999] 5 स्केल 609, पर भरोसा किया गया।

5. शिकायत को ध्यान से पढ़ने पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह किसी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं करती। धारा 418, 419 और 420 के तहत अपराध की सामग्री को शिकायत में आरोपों के आधार पर पूरी तरह से

अनुपस्थित नहीं कहा जा सकता है। केवल इस तथ्य के कारण कि अनुबंध के उल्लंघन के लिए एक उपाय प्रदान किया गया है, यह अपने आप में न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाध्य नहीं करता है कि नागरिक उपचार ही एकमात्र उपलब्ध उपाय है। आपराधिक कानून और नागरिक उपचार दोनों को विभिन्न स्थितियों में अपनाया जा सकता है और वे परस्पर अनन्य नहीं हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से सह-विस्तृत हैं और अनिवार्य रूप से उनकी सामग्री और परिणाम में भिन्न हैं। यह मान लेना अभिशाप है कि जब कोई नागरिक उपचार उपलब्ध है, तो आपराधिक मुकदमा पूरी तरह से वर्जित है क्योंकि दोनों प्रकार की कार्रवाइयां सामग्री, दायरे और प्रदान में काफी भिन्न हैं। [1183-डी-जी]

प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार, [1985] एससीसी सीऔरएल। 180 और डॉ. शर्मा नर्सिंग होम बनाम दिल्ली प्रशासन, [1998] 8 एससीसी 745, पर भरोसा किया गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या.2000 का 233।

सी.और.एल.पी. में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 15.2.99 से। 1998 का क्रमांक 5386।

यू.और. ललित, पी.एन. मिश्रा, एस. नंदा कुमार, एम. दीना दयालन, एन. स्वामीनाथन, एल.के. पांडे और जी. शिवबालामुरुगन अपीलकर्ता की ओर से पी.एस. मिश्रा, और.पी. सिंह, चंद्र शेखर और सुश्री रितु सिंह, उत्तरदाताओं के लिए

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

बनर्जी, जे. छुट्टी दी गई।

शिकायत या आरोप-पत्र को रद्द करने के लिए संहिता की धारा 482 में परिकल्पित अंतर्निहित शक्ति के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग एक अपवाद है, बल्कि एक नियम है और प्रारंभिक चरण में रद्द करने के मामले को दुर्लभ से दुर्लभतम माना जाना चाहिए, इसलिए ताकि अभियोजन में बाधा न पड़े। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के साथ ही गेंद घूमना तय हो जाती है और उसके बाद कानून अपना काम करता है और कानून के प्रावधानों के अनुसार जांच शुरू होती है। अधिकार क्षेत्र वैसे ही सीमित और प्रतिबंधित है और इसका अनुचित विस्तार न तो व्यावहारिक है और न ही आवश्यक है। हालाँकि, शिकायत पर गौर करने पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि शिकायत या आरोप-पत्र में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया किसी अपराध का गठन या खुलासा नहीं करते हैं, जैसा कि आरोप लगाया गया है, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना और कानून के तहत आवश्यक स्थिति से निपटना।

निराश वादियों को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अपनी प्रतिशोध की भावना प्रकट करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाना चाहिए और ऐसी जांच को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह न्याय की अवधारणा के विपरीत है, जो सर्वोपरि है।

इसलिए तथ्यात्मक मैट्रिक्स स्थिति के आकलन के मामले में प्रासंगिक होगा कि क्या 'नागरिक प्रोफ़ाइल' 'आपराधिक संगठन' पर भारी पड़ेगी।

ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 120बी, 418, 415 और 420 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ 17वें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, हैदराबाद की फाइल पर कार्यवाही शुरू करने के खिलाफ, उत्तरदाताओं ने शिकायत को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया और 15 फरवरी, 1999 को विद्वान एकल न्यायाधीश ने 1998 की आपराधिक याचिका संख्या 5386 में शिकायत को रद्द कर दिया और इसलिए याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष अपील में है। मामले से निपटते समय विद्वान एकल न्यायाधीश एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे कि शिकायत आरोपी याचिकाकर्ता द्वारा किए गए किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करती है और इस तरह शिकायत को रद्द करने की याचिका को स्वीकार कर लिया।

तथ्यात्मक स्कोर दर्शाता है कि उत्तरदाताओं ने प्रतिवादी कंपनी द्वारा निर्मित की जा रही विभिन्न फार्मास्युटिकल दवाओं और उत्पादों में बिक्री और उपयोग के लिए थोक में एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड दवा सुरक्षित करने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता से संपर्क किया। यह इस समय है कि याचिकाकर्ता एक निश्चित मामला लेकर आया है, जिसमें एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड के निर्माण के उद्देश्य से याचिकाकर्ताओं को कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के वादे के कारण और इस तरह से किया गया है कि किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। शिकायतकर्ता के कारखाने की विनिर्माण गतिविधि में रुकावट या रुकावट के कारण, शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता ने 31 अगस्त, 1997 को एक समझौता किया, जो अन्य बातों के साथ-साथ नीचे दिया गया है:

"निर्माता को लगातार आपूर्ति बनाए रखने के लिए और निर्माता द्वारा विनिर्माण गतिविधि में

कोई रुकावट/बाधा उत्पन्न न करने के लिए अनुलग्नक 1 में वर्णित कच्चे माल की पर्याप्त

सूची बनाए रखना दूसरे पक्ष की जिम्मेदारी है। "

जैसा कि ऊपर देखा गया है, समझौते के आधार पर और उसका अनुपालन करने में विफलता के आधार पर, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता को लगभग

एक करोड़ की बड़ी राशि का नुकसान हुआ है और नुकसान का कारण विशिष्ट आश्वासन है और प्रतिनिधित्व जो स्पष्ट रूप से झूठा निकला। शिकायतकर्ता के प्रति प्रतिवादी आरोपी व्यक्तियों की ओर से गलत बयानी करना प्रमुख शिकायत रही है और एक निश्चित और विशिष्ट मामला बनाया गया है कि इस तरह की गलत बयानी जानबूझकर की गई थी, क्योंकि आरोपी व्यक्तियों को इस बात की जानकारी थी कि घटना में आपूर्ति प्रभावित नहीं होती है, समझौते के अनुसार, शिकायतकर्ता को गलत नुकसान होने की संभावना है, जैसे-जैसे शिकायत आगे बढ़ती है, पार्टियों के बीच लेनदेन के हित में, आरोपी व्यक्ति रक्षा करने के लिए बाध्य थे। इस बिंदु पर शिकायत के प्रासंगिक अंशों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शिकायत में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित प्रावधान हैं:

(1)"...31.8.1997 के समझौते के खंड 9 में कहा गया है कि दूसरे भाग (ए1 कंपनी) की पार्टी द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति की अनुसूची और पहले भाग (शिकायतकर्ता) की पार्टी द्वारा तैयार उत्पाद की डिलीवरी का समय निर्धारित किया जाएगा। अनुलग्नक III (समझौते के अनुसार) के अनुसार हो।

(ii) 31.8.1997 के समझौते के अनुबंध III से पता चलेगा कि 8500 किलोग्राम के मासिक उत्पादन को सुविधाजनक बनाने और बनाए रखने के लिए शिकायतकर्ता को ए वन द्वारा कच्चे माल डीएल 2 अमीनो बुटानॉल की आपूर्ति 15,210 किलोग्राम या 15.21 एमटीएस. प्रति माह होनी चाहिए या 8.5 एमटीएस. तैयार उत्पाद प्रति माह एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड की होनी चाहिए।

(iii) एक अन्य मुख्य कारक यह है कि शिकायतकर्ता को ए 1 के साथ समझौते के निष्पादन के कारण कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने ए 1 के साथ दिनांक 31.8.1997 को समझौता किया था जिसके तहत शिकायतकर्ता ए 1 द्वारा आपूर्ति किए गए कच्चे माल को थोक दवा एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड में परिवर्तित कर रहा है और इसे निर्धारित रूपांतरण शुल्क पर ए 1 को वापस आपूर्ति कर रहा है।"

(iv) शिकायतकर्ता का कहना है कि ए 1 द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति, विशेष रूप से प्रमुख आयातित कच्चे माल डीएल 2 अमीनो बुटानॉल, समझौते की शुरुआत से ही नियमित नहीं थी। इसकी जानकारी अक्सर A2, A3, A4 और A5 के जरिए अल को दी जाती थी। ए 2 से ए 5 तक ए 1 द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार

पर, शिकायतकर्ता ने समझौते के अनुसार यानी 15,210 किलोग्राम की आपूर्ति के आधार पर इसके उत्पादन की योजना बनाई थी। हर महीने रूपांतरण के लिए A1 द्वारा DL2 अमीनो बुटानॉल, लेकिन A2, A3, A4 और A5 के माध्यम से उनके द्वारा दर्शाए गए कच्चे माल की आपूर्ति करने में अल की जानबूझकर विफलता के कारण शिकायतकर्ता की उत्पादन योजनाएं पूरी तरह से अव्यवस्थित और बाधित हो गईं..

(v) शिकायतकर्ता का कहना है कि उसे एक करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। अभियुक्त द्वारा जानबूझकर की गई चूक के कारण एक करोड़ रु. ए 1 की ओर से इन चूकों को शिकायतकर्ता द्वारा टेलीफोन कॉल के माध्यम से बार-बार आरोपी के ध्यान में लाया गया, विशेष रूप से 15.12.97 और 10.02.98 के फैंक्स संदेश में ए 1 और ए 3 पर।

(vi) शिकायतकर्ता ने 04.04.1998 को ए 2 के साथ एक बैठक की जिसमें ए 3 ने भी भाग लिया। 04.04.98 को आयोजित इस बैठक में, ए 2 और ए 3 शिकायतकर्ता द्वारा बताई गई स्थिति से सहमत हुए और उन्होंने अभ्यावेदन दिया कि ए 1 द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति, विशेष रूप से महत्वपूर्ण कच्चे माल डीएल 2 अमीनो बुटानॉल,

तैयार उत्पाद के 8 मीट्रिक टन के उत्पादन को सक्षम करने के लिए इसे नियमित रूप से जारी रखा जाएगा। शिकायतकर्ता ने ए 1 के द्वारा ए 2 और ए 3 तक इन अभ्यावेदनों को उसी दिन लिखित रूप में लिख दिया और पत्र दिनांक 4.4.98 से ए 1 से ए 3 तक लिखा। इस पत्र की सामग्री का A1 द्वारा खंडन नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इसके बावजूद, आरोपी जानबूझकर 4.4.98 को शिकायतकर्ता को दिए गए अपने अभ्यावेदन पर कार्रवाई करने में विफल रहे और इस तरह शिकायतकर्ता को भारी नुकसान पहुंचाते रहे...

(vii) शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपी के साथ अपनी बातचीत और चर्चा में, वह A2, A3, A4, A5 और A6 को संकेत दे रहा था कि मामले में A1 अपने अभ्यावेदन पर खरा नहीं उतर सका, जिसने शिकायतकर्ता को भारी नुकसान होने पर, इस खंड 15 को लागू किया जा सकता है और शिकायतकर्ता द्वारा ए 1 को 2 महीने का नोटिस देकर समझौता समाप्त किया जा सकता है। लेकिन अभियुक्त, इन अवसरों पर, शिकायतकर्ता को इस प्रावधान को लागू न करने के लिए मनाएगा और शिकायतकर्ता को आगे अभ्यावेदन देगा कि कच्चे माल की आपूर्ति अब से सहमत स्तर पर रखी जाएगी। हालाँकि, इन अभ्यावेदनों पर अभियुक्त द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, जबकि दूसरी ओर, इन अभ्यावेदनों पर विश्वास करते हुए, शिकायतकर्ता ने उत्पादन का कार्यक्रम बनाया, लेकिन सामग्री के बिना छोड़ दिया

गया, निष्क्रिय श्रम ले जाने वाले एक निष्क्रिय संयंत्र को पकड़कर रखा गया और इस प्रकार भारी खर्च हुआ और्थिक हानि....

(viii) शिकायतकर्ता अब समझता है कि उपरोक्त गलत बयानी अभियुक्तों द्वारा केवल शिकायतकर्ता को भारी नुकसान पहुंचाने और उन्हें अपंग बनाने के उद्देश्य से की गई थी क्योंकि अभियुक्त स्वयं अपनी सुविधाओं में थोक दवा एथमब्युटोल का निर्माण करने की योजना बना रहे थे। हाइड्रोक्लोराइड और शिकायतकर्ता को उत्पादन से बाहर रखकर उन्हें बर्बाद करके प्रतिस्पर्धा से बाहर करना चाहता था, जिसे अभियुक्त ने सहमत स्तरों पर कच्चे माल की आपूर्ति का गलत इन अभ्यावेदनों के अनुसार प्रतिनिधित्व करके और फिर जानबूझकर असफल होने और उसके अनुसार कार्य करने से चूक कर हासिल किया।

(ix) शिकायतकर्ता को भी अभ्यावेदन से आश्वस्त किया गया अभियुक्त को समझौते के खंड 15 को लागू करने से रोकने और इसे रद्द करने का आदेश दिया गया, जिससे उसके नुकसान को कुछ हद तक कम किया जा सकता था। अभियुक्त के उपरोक्त कृत्य स्पष्ट रूप से धारा 415 आई.पी.सी के तहत दंडनीय अपराध की सामग्री को आकर्षित करते हैं।

(x) आरोपियों का इरादा बेईमानी का था और ऐसे इरादे से ही शिकायतकर्ता कंपनी को धोखाधड़ी और बेईमानी से समझौता करने के लिए प्रेरित किया गया

था। दिनांक 31.8.97. शिकायतकर्ता के तीन अधिकारियों के खिलाफ ए 1 की ओर से ए 6 द्वारा दर्ज की गई शिकायत से आरोपी के बेईमान इरादे का पता चलता है।

(xi) अभियुक्तों को पूरी तरह से पता था कि शिकायतकर्ता एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड का एक प्रतिष्ठित निर्माता है और भारत और विदेशी बाजारों में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है। आरोपी स्वयं एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड के उत्पादन में प्रवेश करने पर विचार कर रहे थे और शिकायतकर्ता से प्रतिस्पर्धा को खत्म करना चाहते थे जिन्होंने बाजार में अपना नाम स्थापित किया था। इसे ध्यान में रखते हुए, आरोपी ने गलत लाभ कमाने और शिकायतकर्ता को गलत नुकसान पहुंचाने के लिए, उपरोक्त तरीके से कार्य किया, शिकायतकर्ता को (अभियुक्त द्वारा) अभ्यावेदन के माध्यम से रूपांतरण कार्य करने के लिए प्रेरित किया और परिणामस्वरूप इसके उत्पादन का समय निर्धारित किया। तदनुसार और फिर जानबूझकर अभ्यावेदन के अनुसार कार्य करने में विफल रहा जिससे शिकायतकर्ता को भारी नुकसान हुआ।

(xii) शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि लेकिन समझौते में प्रवेश के समय आरोपी द्वारा की गई झूठी अभ्यावेदन के लिए दिनांक 31.8.97, यह (शिकायतकर्ता) इस अनुबंध में शामिल नहीं हुआ होगा। अभियुक्त के उपरोक्त कृत्यों ने शिकायतकर्ता की और्थिक स्थिति को बर्बाद कर दिया और अभियुक्त के इन

कृत्यों के कारण उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। शिकायतकर्ता का कहना है कि अभियुक्त के उपरोक्त कृत्य स्पष्ट रूप से आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत आते हैं...

(xiii) इस शिकायत के पूर्ववर्ती पैराग्राफ स्पष्ट रूप से प्रकट करेंगे कि अभियुक्त, जो दिनांक 31.8.97 के समझौते के तहत लेनदेन में शिकायतकर्ता के हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य हैं, ने न केवल शिकायतकर्ता को धोखा दिया है, इसे गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया, लेकिन लेन-देन में शिकायतकर्ताओं के हित की रक्षा करने में भी असफल रहे। इसलिए आरोपियों को आईपीसी की धारा 418 के तहत दंडित किया जा सकता है...

मेडचल केमिकल एण्ड फार्मा प्राईवेट लिमिटेड बनाम मैसर्स बायोलोजिकल ई. लिमिटेड [बनर्जी जे.] 1177

(xiv) शिकायतकर्ता का कहना है कि ऊपर जो कुछ भी कहा गया है और निर्धारित किया गया है, उससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ए1 से ए6 ने एक-दूसरे के साथ

आपराधिक साजिश रची और सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हुए उपरोक्त अपराध अन्तर्गत धारा 415 व 420 आई.पी.सी. के तहत अपराध किया है। पत्र पत्राचार, शिकायत और समझौते से संबंधित दस्तावेज दिनांक 31.8.97 साबित करेगा कि ए2 से ए6 ने ए1 के मामलों में और विशेष रूप से, समझौते दिनांक 31.8.97 के तहत लेनदेन से संबंधित मामलों में बहुत अधिक भाग लिया है।

इस लंबे वर्णन को शायद टाला जा सकता था, लेकिन इस तथ्य के कारण ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने केवल यह दर्ज किया है:

"ऐसा प्रतीत होता है कि एक समझौते के तहत आरोपी शिकायतकर्ता को उत्पादन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए बाध्य थे, जो वे करने में विफल रहे। मुझे शिकायत में कोई भी आरोप नहीं मिला-वादपत्र जो एक आपराधिक अपराध का खुलासा करेगा"।

मामले में आगे बढ़ने से पहले, आइए अब प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित अपराधों से निपटें। पहला कथित अपराध आईपीसी की धारा 415 के अर्थ के अंतर्गत 'धोखाधड़ी' का है। सुविधा के लिए धारा 415 इस प्रकार है:

415. धोखा देना-जो कोई किसी व्यक्ति को धोखा देकर, कपटपूर्वक या बेईमानी से उस व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को किसी व्यक्ति को देने के लिए प्रेरित करता है, या सहमति देने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति को बनाए रखेगा, या जानबूझकर इस तरह से धोखा देने वाले व्यक्ति को ऐसा करने या न करने के लिए प्रेरित करता है ऐसा कुछ भी जो वह नहीं करेगा या छोड़ देगा यदि उसे धोखा न दिया गया हो, और जिस कार्य या चूक से उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को क्षति या नुकसान होने की संभावना हो, उसे "धोखा" कहा जाता है।

स्पष्टीकरण-इस धारा के अर्थ में तथ्यों को बेईमानी से छिपाना एक धोखा है।

शिकायत आईपीसी की धारा 418 के तहत भी बताई गई है। जो इस प्रकार है:

418. इस जानकारी के साथ धोखा करना कि गलत तरीके से उस व्यक्ति को नुकसान हो सकता है जिसके हितों की रक्षा करने के लिए अपराधी बाध्य है- जो कोई भी इस ज्ञान के साथ धोखा करता है कि उसके द्वारा उस व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने की संभावना है जिसके लेनदेन में धोखाधड़ी संबंधित हित है, जिसकी रक्षा करने के लिए वह या तो कानून द्वारा या कानूनी अनुबंध

द्वारा बाध्य था, उसे कारावास की सजा दी जाएगी, या तो एक अवधि के लिए विवरण जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ।

शिकायत में आईपीसी की धारा 420 के तहत किए गए अपराध का भी आरोप लगाया गया है, जो इस प्रकार है:

420. धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए उत्प्रेरित करना- जो कोई धोखा देता है और इस तरह बेईमानी से धोखेबाज व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को किसी व्यक्ति को देने के लिए प्रेरित करता है, या किसी मूल्यवान सुरक्षा के पूरे या किसी हिस्से को बनाने, बदलने या नष्ट करने, या कुछ भी जो हस्ताक्षरित या मुहरबंद है, और जो परिवर्तित होने में सक्षम है मूल्यवान सुरक्षा में, किसी भी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

धारा 415 के तहत अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री को इस न्यायालय द्वारा रामजस बनाम उत्तरप्रदेश राज्य, [1970] 2 एससीसी 740 के मामले में स्पष्ट रूप से निपटाया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार देखा:

"धोखाधड़ी का अपराध गठित करने के लिए आवश्यक सामग्रियां हैं-

(i) कोई कपटपूर्ण या बेईमान प्रलोभन होना चाहिए व्यक्ति को धोखा देकर;

(ii) (ए) इस प्रकार धोखा खाए गए व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, या यह सहमति देने के लिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति को बनाए रखेगा, या

(बी) इस प्रकार धोखा खाए व्यक्ति को जानबूझकर ऐसा कुछ करने या करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए जो वह करेगा या नहीं करेगा यदि वह इतना धोखा नहीं खाया था; और

(iii) (बी) के अंतर्गत आने वाले मामलों में, कार्य या चूक ऐसा होना चाहिए जो प्रेरित व्यक्ति के शरीर, दिमाग, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचा सकता है।

जबकि धारा 415 धोखाधड़ी का अपराध है, धारा 418 इस ज्ञान के साथ धोखाधड़ी से संबंधित है कि गलत तरीके से उस व्यक्ति को नुकसान हो सकता है जिसके हितों की रक्षा करने के लिए अपराधी बाध्य है और धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति के वितरण के लिए प्रेरित करना है। धारा 418 और 420 के प्रावधानों को दोषी ठहराने के लिए, वादा करते समय, वादा करना एक आवश्यकता और एक आवश्यक घटक है और बाद में वादे को पूरा करने में विफलता धारा 418 या 420 के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगी। मेन्स रिया धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के अपराध के आवश्यक तत्वों में से एक है। तथ्य

की बात के रूप में धारा 415 का चित्रण (जी) स्थिति को इतना स्पष्ट कर देता है कि यह इंगित करने के लिए कि केवल एक समझौते का उल्लंघन करने में विफलता को अपराध नहीं माना जाएगा। धोखाधड़ी, लेकिन अनुबंध के उल्लंघन के लिए केवल एक नागरिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है और यह वह अवधारणा है जिस पर स्पष्ट रूप से विद्वान एकल न्यायाधीश ने विचार किया है। लेकिन क्या शिकायत के लंबे पुनरुत्पादन में ऊपर बताई गई तथ्यात्मक स्थिति विद्वान न्यायाधीश की टिप्पणियों का समर्थन कर सकती है, इसका उत्तर महत्वपूर्ण है लेकिन ऐसा करने से पहले सीऔरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों के संबंध में एक अन्य पहलू पर विचार करें। ध्यान देना चाहिए। जैसा कि यहां पहले उल्लेख किया गया है, इस शक्ति का प्रयोग सावधानी और सावधानी के साथ और संयमित ढंग से किया जाना है और ऐसा एक से अधिक अवसरों पर किया गया है।

प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार के मामले में, [1985] एससीसी सीऔरएल. 180 इस न्यायालय ने बताया कि उच्च न्यायालय को सीऔरपीसी की धारा 482 के तहत अपने विवेक का प्रयोग बहुत संयम से करना चाहिए।

एल.वी. में जाधव बनाम शंकरराव अबासाहेब पवार, एआईऔर (1983) एससी 1219 - [1983] 4 एससीसी 231 = [1983] एससीसी सीऔरएल. 813 इस न्यायालय ने देखा:

"हम यह कहने से बच नहीं सकते कि उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द करने के लिए शुरुआत में ही अपनी अंतर्निहित शक्तियों को लागू करने से इनकार कर दिया होगा, क्योंकि इन शक्तियों का प्रयोग संयमित और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए जब यह विश्वास करने का कारण हो कि एक नागरिक को परेशान करने के लिए कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है।"

हालाँकि, रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है और यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, शिकायत की संपूर्णता की जांच शिकायत में लगाए गए आरोप के आधार पर की जाएगी और उस स्तर पर उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी, इस मामले में जाने या इसकी सत्यता की जांच करने का कोई अधिकार या क्षेत्राधिकार नहीं है। शिकायत में जो भी दिखाई देता है, उस पर बिना किसी आलोचनात्मक जांच के विचार किया जाएगा। लेकिन शिकायत पर अपराध प्रथम दृष्टया प्रकट होना चाहिए। श्रीमती नागव्वा बनाम

वीरन्ना शिवलिंगप्पा कोन्जाल्गी, [1976] 3 एससीसी 736] कानून

के अवलोकन में उपरोक्त कथन का समर्थन करते हैं।

(1) जहां शिकायत में लगाए गए आरोप या उनके समर्थन में दर्ज किए गए गवाहों के बयान अंकित मूल्य पर लेने पर आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है या शिकायत उस अपराध के आवश्यक तत्वों का खुलासा नहीं करती है, अभियुक्त खिलाफ आरोप लगाया गया है।

(2) जहां शिकायत में लगाए गए आरोप स्पष्ट रूप से बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, इसलिए कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है;

(3) जहां जारी करने की प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग किया गया विवेक मनमाना है, जो या तो बिना किसी सबूत या ऐसी सामग्री पर आधारित है जो पूरी तरह से अप्रासंगिक या अस्वीकार्य है; और

(4) जहां शिकायत मौलिक कानूनी दोषों से ग्रस्त है, जैसे मंजूरी की कमी, या कानूनी रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिकायत की अनुपस्थिति आदि।

हमारे द्वारा उल्लिखित मामले पूरी तरह से उदाहरणात्मक हैं और उन आकस्मिकताओं को इंगित करने के लिए पर्याप्त दिशानिर्देश प्रदान करते हैं जहां उच्च न्यायालय कार्यवाही को रद्द कर सकता है।

विचाराधीन मामले में, यदि हम शिवलिंगप्पा के मामले (सुप्रा) में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, तो क्या यह कहा जा सकता है कि शिकायत में लगाए गए आरोप आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाते हैं और न ही यह किसी के अवयवों का खुलासा करता है। अभियुक्त के विरुद्ध कथित अपराध या के आरोप स्पष्ट रूप से बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, इसलिए कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है। वर्तमान मामले में, हालाँकि, जैसा कि ऊपर देखा गया है, शिकायत उठाए गए प्रश्नों पर विश्वास नहीं करती है। यह अब अच्छी तरह से तय हो गया है और किसी को इस संबंध में विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, न ही हमारा वर्तमान में ऐसा करने का इरादा है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों को खारिज करना होगा जैसा कि ऊपर देखा गया है, इसे प्रथम दृष्टया स्वीकार कर लिया गया है और इसकी सत्यता या मिथ्या पर न्यायालय द्वारा प्रारंभिक चरण में विचार नहीं किया जाएगा: शिकायत में लगाए गए आरोप सही थे या नहीं, इसका निर्णय अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर किया जाना है। नागपुर स्टील एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड बनाम पी. राधाकृष्ण, [1997] एससीसी सीओरएल 1073 के मामले में

परीक्षण और इस स्कोर पर टिप्पणियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में इस न्यायालय ने कहा:

"3. हमने शिकायत का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। हमारी राय में यह नहीं कहा जा सकता है कि शिकायत ने किसी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं किया है। केवल इसलिए कि अपराध एक वाणिज्यिक लेनदेन के दौरान किया गया था, यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं होगा शिकायत में मुकदमे की आवश्यकता नहीं थी। शिकायत में लगाए गए आरोप सही थे या नहीं, इसका निर्णय शिकायत मामले में सुनवाई के दौरान दिए जाने वाले सबूतों के आधार पर किया जाना था। यह निश्चित रूप से ऐसा मामला नहीं था जिसमें आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए जिसे कम कर दिया गया है। शिकायत को रद्द करने से न्याय की गंभीर विफलता हुई है। इसलिए, मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना, हम इस अपील की अनुमति देते हैं और उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को रद्द करते हैं और शिकायत को बहाल करते हैं। विद्वान परीक्षण मजिस्ट्रेट शिकायत के साथ आगे बढ़ेंगे और कानून के अनुसार शीघ्रता से इसका निपटान करेंगे।

ज्ञात हो कि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग के मामले में, एकमात्र आवश्यकता यह देखना है कि क्या कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का पूर्ण दुरुपयोग होगा। आपराधिक प्रक्रिया संहिता में जांच, आरोप और मुकदमे के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया शामिल है, और ऐसी स्थिति में, उच्च न्यायालय कानून की ज्ञात प्रक्रिया पर रोक लगाना चाहता है, उच्च न्यायालय को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए शिकायत को रद्द करने में देखभाल और बहुत सावधानी बरतें। हाल ही में, ट्राइसन्स केमिकल इंडस्ट्री बनाम राजेश अग्रवाल और अन्य, (1999) 5 स्केल 609 में इस न्यायालय ने कहा:

"5. उच्च न्यायालय में प्रतिवादी के वकील ने मुख्य रूप से दो तर्क रखे। पहला यह कि विवाद पूरी तरह से नागरिक प्रकृति का है और इसलिए किसी भी अभियोजन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, और दूसरा यह कि प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, गांधीधाम के पास शिकायत पर विचार करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दोनों तर्कों को मंजूरी दे दी है और शिकायत और उस पर मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है।

6. पहले मामले में एकल न्यायाधीश ने बताया कि पार्टियों के बीच आए समझौता ज्ञापन में एक विशिष्ट खंड था, कि किसी भी लेनदेन के संबंध में उनके

बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:

"इसके अलावा प्रसंस्कृत सोयाबीन की आपूर्ति शिकायतकर्ता कंपनी द्वारा बिना किसी आपत्ति के प्राप्त की गई थी और उसे शिकायतकर्ता-कंपनी द्वारा निर्यात किया गया था। यह सवाल कि क्या शिकायतकर्ता-कंपनी को उसके द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार नुकसान हुआ था, इस पर फैसला सुनाया जाना है। सिविल न्यायालय आपराधिक अभियोजन का विषय नहीं हो सकता।"

7. यह न्यायालय बार-बार इंगित करता रहा है कि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एफआईओर या शिकायत को रद्द करना बहुत ही चरम अपवादों तक सीमित होना चाहिए (हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, [1992] सप्लिमेंट के अनुसार 1 एससीसी 335 और राजेश बजाज बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली, [1999] 3 एससीसी 259)

8. पिछले संदर्भित मामले में इस अदालत ने यह भी बताया कि केवल इसलिए कि किसी अधिनियम की नागरिक प्रोफाइल है, उसे आपराधिक संगठन से वंचित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम निम्नलिखित टिप्पणियाँ उद्धृत करते हैं:

"हो सकता है कि वर्तमान शिकायत में बताए गए तथ्य किसी वाणिज्यिक लेन-देन या पैसे के लेन-देन का भी खुलासा करें। लेकिन यह मानने का शायद ही

कोई कारण है कि इस तरह के लेन-देन से धोखाधड़ी का अपराध टल जाएगा। वास्तव में वाणिज्यिक और धन लेन-देन में कई धोखाधड़ी हुई थी।

9. हम इस तर्क की सराहना करने में असमर्थ हैं कि प्रावधान विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए समझौते में शामिल किया गया कानून, विवादित कृत्य के अपराध होने पर आपराधिक मुकदमा चलाने का एक प्रभावी विकल्प है। मध्यस्थता समझौते के उल्लंघन से प्रभावित पक्ष को राहत देने का एक उपाय है, लेकिन मध्यस्थ किसी ऐसे कार्य का परीक्षण नहीं कर सकता है जो अपराध की श्रेणी में आता है, भले ही वही कार्य समझौते के तहत किसी भी कार्य के निर्वहन से जुड़ा हो सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा शिकायत को शुरुआत में ही खारिज करने के ये अच्छे कारण नहीं हैं। जांच एजेंसी को आरोपों के पूरे दायरे में जाने और अपने निष्कर्ष पर पहुंचने की आजादी होनी चाहिए थी। इस तरह की जांच को पहले से शुरू करना केवल बहुत गंभीर मामलों में ही उचित होगा, जैसा कि हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (सुप्रा) में संकेत दिया गया है।"

शिकायत को ध्यान से पढ़ने पर, हमारे विचार से, यह नहीं कहा जा सकता कि शिकायत किसी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं करती है। धारा 415, 418 और 420 के तहत अपराध की सामग्री को शिकायत में आरोपों के आधार पर पूरी तरह से अनुपस्थित नहीं कहा जा सकता है। हालाँकि, हम यह

जोड़ने में जल्दबाजी करते हैं कि शिकायत में लगाए गए आरोप अन्यथा सही हैं या नहीं, इसका निर्णय शिकायत मामले में मुकदमे के दौरान दिए जाने वाले साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए, लेकिन केवल इस तथ्य के कारण कि कोई उपाय है अनुबंध के उल्लंघन के लिए प्रावधान किया गया है, जो अपने आप में न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम नहीं बनाता है कि अपीलकर्ता के लिए नागरिक उपचार ही एकमात्र उपाय है। आपराधिक कानून और नागरिक कानून दोनों विभिन्न स्थितियों में उपाय अपनाए जा सकते हैं। तथ्य की बात के रूप में, "वे परस्पर अनन्य नहीं हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से सह-व्यापक हैं और अनिवार्य रूप से उनकी सामग्री और परिणाम में भिन्न हैं। आपराधिक कानून का उद्देश्य उस अपराधी को दंडित करना है जो किसी व्यक्ति, संपत्ति या राज्य के खिलाफ अपराध करता है जिसके लिए अपराध साबित होने पर आरोपी को उसकी स्वतंत्रता और कुछ मामलों में तो उसके जीवन से भी वंचित कर दिया जाता है। हालाँकि, यह आगजनी, दुर्घटना आदि जैसे मामलों में गलत काम करने वाले पर मुकदमा चलाने के नागरिक उपचारों को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। यह मान लेना अभिशाप है कि जब एक नागरिक उपचार उपलब्ध होता है, तो एक आपराधिक मुकदमा पूरी तरह से वर्जित होता है। प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार

(सुप्रा) के मामले में दो प्रकार की कार्यवाहियां सामग्री, दायरे और प्रदान में काफी भिन्न हैं।

उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मिश्रा, जो यहां आरोपी व्यक्ति हैं, ने इस न्यायालय के निर्णयों पर दृढ़ता से भरोसा किया, जिसमें

डॉ. शर्मा नर्सिंग होम बनाम दिल्ली प्रशासन, [1998] 8 एससीसी 745 के मामले में, जिसमें इस न्यायालय ने कहा: "हमने पाया है कि दोनों विद्वान अदालतों ने अपने निष्कर्षों को केवल धोखे पर आधारित किया है और इस सवाल पर विचार नहीं किया है कि क्या शिकायतकर्ता और उसके साथियों ने आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध के अन्य आवश्यक घटक का खुलासा किया, अर्थात्, बेईमान प्रलोभन।" श्री मिश्रा ने डॉ. शर्मा के मामले (सुप्रा) पर भरोसा करते हुए यह भी तर्क दिया कि आई.पी.सी. की धारा 24 में "बेईमानी" शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ जानबूझकर गलत लाभ या गलत हानि का कारण है। यह शिकायतकर्ता का विशिष्ट मामला है कि लेन देन की शुरुआत से ही आरोपी व्यक्तियों की और से शिकायतकर्ता को गलत नुकसान पहुंचाने का एक निश्चित इरादा था।

हालाँकि, मामले के तथ्यात्मक पहलू पर विचार करते हुए, हम बिना किसी हिचकिचाहट के यह कहते हैं कि विचाराधीन मामले में शामिल मुद्दा ऐसा मामला

नहीं है जिसमें आपराधिक मुकदमे को छोटा कर दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार, हम मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना अपील की अनुमति देते हैं और उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को रद्द करते हैं और शिकायत को बहाल करते हैं। विद्वान ट्रायल मजिस्ट्रेट शिकायत के साथ आगे बढ़ेगा और कानून के अनुसार अत्यंत शीघ्रता से उसका निपटान करेगा। हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाए कि इस निर्णय में उपरोक्त टिप्पणियों को हमारी किसी राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

अपील की अनुमति.

यह अनुवाद ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रियंका मीना (और.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।